

डाकघर अधिनियम 2023

प्रलिस के लयः

[डाकघर अधिनियम, 1898](#), [सारवजनक वयवस्था](#), [आपातकाल](#), [सारवजनक सुरक्षा](#), [भू-राजसव](#), [वाक और अभवयकतकी सवतंतरता](#), [नजिता का अधकार](#) ।

मेन्स के लयः

डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमयः ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चरचा में कयः?

हाल ही में [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898](#) को नरिसत करते हुए [डाकघर अधिनियम 2023](#) लागू हुआ ।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य वशेषताएँ कय हैं?

- **वस्तुओं का अवरोधन और नरिोधः**
 - **धारा 9:** यह प्रावधान केंद्र को कसी भी अधकारी को राज्य सुरक्षा, वदशी संबध आद से संबधति कारणों से कसी भी डाक वस्तु को रोकने या रोकने के लयि अधकृत करने की अनुमतदता है ।
 - जनि वस्तुओं में प्रतबिधति सामान होने का संदेह हो या जनि पर सीमा शुलक लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा शुलक प्राधकारयः को साँपा जा सकता है ।
- **दायतव से छूटः**
 - **धारा 10:** डाकघर और उसके अधकारयः को सेवाएँ प्रदान करने के दौरान हानि, गलत वतरण, देरी या कषतके लयि देयता से छूट दी गई है, सविय जैसा कनरिधारति कयि गया हो ।
- **दंड और अपराधों का उनमूलन:** नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लखिति सभी दंड और अपराधों को समाप्त कर देता है, जनिमें डाक अधकारयः द्वारा कदाचार, धोखाधडी तथा चोरी से संबधति दंड एवं अपराध भी शामिल हैं ।
 - इसमें भुगतान न कयि गए सेवा शुलक को भू-राजसव के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान शामिल है ।
- **धारा 7 के अंतरगत जुरमाना:** प्रत्येक वयकत जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है, उसे ऐसी सेवा के संबध में शुलक का भुगतान करना होगा ।
- **केंद्र की वशिषिटता को हटाना:** नया अधिनियम पत्रों को पहुँचाने के लयि केंद्र के वशिषाधकार को हटा देता है, यह वशिषाधकार 1980 के दशक में नजिी कूरयिर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अपरचलति हो गया था ।
 - यह अधिनियम अब स्पष्ट रूप से नजिी कूरयिर सेवाओं को अपने वनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की वशिषिटता की हानिको मान्यता देता है और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं, बलककिसी भी डाक सामगरी को बंद एवं रोकने के दायरे का वसितार करता है ।
- **डाक सेवा महानदिशक:** नया अधिनियम डाक सेवा के महानदिशक को वभिन्न अतरिकित सेवाएँ प्रदान करने के लयि आवश्यक गतवधिथः से संबधति वनियम बनाने के लयि अधकृत करता है, जैसा ककेंद्र सरकार द्वारा नरिधारति कयि जा सकता है, साथ ही इन सेवाओं हेतु शुलक नरिधारति करने के लयि भी अधकृत करता है ।
 - यह वधियक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली कसी भी सेवा के लयि नरिधारति शुलक में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है ।
- **पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड:** अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है ककि "केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड के उपयोग के लयि मानक नरिधारति कर सकती है" ।
 - यह प्रावधान एक दूरदर्शी अवधारणा है और साथ ही कसी परसिर की सटीक पहचान के लयि भौगोलक नरिदेशांक के आधार पर भौतिक पते को डजिटल कोड से परविरतति कर देगा ।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1898 को लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली **डाक सेवाओं के वनियमन का प्रावधान** करता है।
- यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।

डाकघर अधिनियम 2023 में क्या मुद्दे हैं?

- **डाक सेवाओं का वनियमन कूरियर सेवाओं से भिन्नताएँ:** **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** भारतीय डाक द्वारा सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह नज्जी कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम, 2023 जो वर्ष 1898 के अधिनियम को प्रतस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव से मूल अधिकारों का उल्लंघन:** वधियक में डाक वस्तुओं के अंतरोधन के वरिद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नरिदष्टि नहीं किया गया है। इससे **नजिता के अधिकार** और **वाक् एवं अभवियकृत सिवातंत्र्य** के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
 - दूरसंचार के अंतरोधन के मामले में **पुल (PUC) (1996)** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने अभनिरिधारति किया कि अंतरोधन की शक्ती को वनियमति करने के लिये एक उचित एवं सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिये।
 - अन्यथा **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक् एवं अभवियकृत सिवातंत्र्य) और **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में नजिता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।
- **'आपातकाल' का आधार उचित प्रतबिंधों से परे है:** 1898 अधिनियम की ही तरह, वर्तमान अधिनियम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परभाषति नहीं किया गया है।
- **सेवाओं में चूक की दशा में दायतिव से छूट:** अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के वपिरीत है, जसिमरेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से माल की हानि, कषती, डलीवरी न होने और करिया वापसी जैसी शकियातों का समाधान किया जाता है।
- **सभी अपराधों और दंडों को हटाना:** वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की कैद, जुमाना या दोनों से दंडनीय था। इसके वपिरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के वरिद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की नजिता के अधिकार पर प्रतकिल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल किया जाना:** इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषित वस्तुओं के अवरोधन के लिये स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू किये जाने की आवश्यकता है।
 - इसमें वाक् एवं अभवियकृत की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की नजिता के अधिकार की रक्षा के लिये **नरिक्षण तंत्र, न्यायिक वारंट** तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल होना चाहिये।
- **अवरोधन के आधार को परभाषति करना:** अवरोधन के आधारों को **परषिकृत और स्पष्ट** रूप से परभाषति करें, विशेष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनिश्चित हो कि यह संवधान के तहत युक्तियुक्त नरिबंधों के साथ संरेखित हो।
 - **2005** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि **जब गोपनीय दस्तावेज़ बैंक को दिये जाते हैं या व्यक्तगित सामान डाकघर को दिये जाते हैं तो नजिता का अधिकार** बरकरार रहता है तथा किसी भी तलाशी एवं ज़बती के लिये लिखित कारणों की आवश्यकता होती है।
- **संतुलित दायतिव ढाँचा:** डाकघर की स्वतंत्रता और कार्यकुशलता को खतरे में डाले बिना उत्तरदायतिव के लिये स्पष्ट नियम नरिधारति करके उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।
 - सक्षम प्राधिकारियों को 'सद्भावना' खंड के बिना अवरोधन शक्तियों के किसी भी जानबूझकर दुरुपयोग के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।
- **अनधिकृत उद्घाटन को संबोधित करना:** उपभोक्ता गोपनीयता की रक्षा के लिये डाक को अनाधिकृत रूप से खोलने पर डाक अधिकारियों को दंडित करने तथा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी के लिये व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने के लिये कानून बनाना।

दृष्टांभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डाकघर अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के संदर्भ में गोपनीयता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने नजिता के अधिकार को भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 16
- (c) अनुच्छेद 19
- (d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/post-office-act-2023>

